

# अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की जवाबदेही की पड़ताल



भारत में 3.1 मिलियन से अधिक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) हैं; संख्या देश में स्कूलों की संख्या, अस्पतालों की संख्या और पुलिस कर्मियों की संख्या से बहुत बड़ी है। भारत में लगभग 22400 एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत हैं।

इस साल एक मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक बयान में, जिसमें कहा गया है कि भारत में काम करने वाले और एफसीआरए के तहत पंजीकृत एनजीओ ने पिछले 4 वर्षों में विदेशों से 50,975 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्राप्त किया है और सबसे अधिक दान यूएसए से प्राप्त किया गया था, 19941 करोड़।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2016-17 में लगभग 18,304 गैर सरकारी संगठनों को 15,355 करोड़ मिले; 2017-18 में 18,235 एनजीओ को 16,940 करोड़ मिले; 2018-19 में 17,540 एनजीओ को 16,490 करोड़ और 2019-20 में 3,475 एनजीओ को 2,190 करोड़ मिले।

भारत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 20,600 गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने एफसीआरए के तहत भारी दान प्राप्त किया, लेकिन वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। भारत में कई गैर सरकारी संगठनों के कामकाज के बारे में गंभीर संदेह हैं। सबसे पहले, आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) ने गंभीर संदेह उठाया जब उन्होंने विदेशी फंडिंग के बारे में आरोप लगाया की कुछ जनहित याचिका इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी परियोजना को रोकने या निजी उद्योग को बंद करने से संबंधित हो सकती है। यहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी मार्च 2013 में यह कहकर संदेह जताया था, “अधिकांश निजी तथाकथित परोपकारी संगठन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। मौजूदा गैर सरकारी संगठनों में से 99% धोखाधड़ी और केवल पैसा कमाने के उपकरण हैं। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रत्येक सौ एनजीओ में से केवल एक ही उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके लिए वे स्थापित किए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास के लिए काम करने के लिए चिंता और प्रतिबद्धता होना अच्छा है, लेकिन अगर यह पर्यावरण के क्षरण या स्थानीय लोगों को नुकसान के बारे में किसी ठोस सबूत के बिना विकास गतिविधियों के लिए बाधाएं पैदा कर रहा है और कोई समाधान नहीं है जिससे लोगों और सरकार को फायदा हो सामाजिक और आर्थिक रूप से, तब इरादा वास्तव में मायने रखता है और एनजीओ के कामकाज के बारे में स्पष्ट संदेह दिमाग में आता है।

कुछ गैर सरकारी संगठनों के आंदोलन के बाद स्टर्लाइट तूतीकोरिन संयंत्र को बंद कर दिया गया है। क्या दुनिया भर में तांबे का उत्पादन बंद हो गया है? कई आंदोलन और जनहित याचिका (पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन) फाइलिंग पहले भी हुई है, जिसने परियोजना में देरी या रोक लगा दी या कारखानों

को बंद कर दिया, निवेशकों की नजर में सरकार और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश को भारी नुकसान हुआ और जीडीपी और समग्र रूप से प्रभावित विकास में देरी हुई। खराब आर्थिक प्रदर्शन के कारण बेरोजगारी में वृद्धि, जीवन स्तर का खराब होना, सामाजिक अशांति का बढ़ना। इरादा ऐसा समाधान खोजने का होना चाहिए जो पर्यावरण और मानव जाति के अनुकूल हो, कारखाने या किसी प्रोजेक्ट को बंद करना पहली नजर में सही समाधान नहीं है। हम हालांकि अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं; एनजीओ द्वारा मामले को सही तरीके से अदालत के सामने पेश करने की जरूरत है ताकि हमारी अदालतों द्वारा सही समाधान सुझाया जा सके।

एक भारतीय के रूप में हम पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों से क्या उम्मीद करते हैं।

• भारत पर्यावरण की बेहतरी के लिए गंभीरता से काम कर रहा है, सौर ऊर्जा एक ऐसी ही कहानी है, जो 100 गीगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं और पेरिस समझौते के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एनजीओ सरकारी एजेंसियों के अच्छे काम को को फैलने में मदद करेंगे और उन्हें प्राप्त होने वाले भारी विदेशी फंडिंग के साथ कस्बों और गांवों में अधिकतम क्षमता स्थापित करना संभव बनाएंगे। सौर ऊर्जा के लिए काम कर रही भारतीय कंपनियों को दुनिया भर में बाजार में उतारें ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। यह पर्यावरण की बेहतरी के लिए मददगार होगा यदि ये अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ चीन और अमेरिका जैसे देशों में सौर ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए काम करते हैं, जो सबसे अधिक कार्बन फुटप्रिंट पैदा करते हैं।

• चूंकि गरीबों और ग्राम विकास के लिए एन जी ओ द्वारा भारी मात्रा में धन एकत्र किया जाता है, क्या इस मुद्दे में वे मदद कर सकते हैं, गांवों में अधिकांश महिलाएं चूल्हे का उपयोग करके खाना बनाती हैं, जिससे वनों की कटाई होती है और चूल्हे से निकलने वाला धुआं बहुत हानिकारक है जो बड़ी बीमारियों को ट्रिगर करता है। वनों की कटाई को कम करने और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार ने इन महिलाओं को आठ करोड़ से अधिक एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए हैं। क्या एनजीओ नियमित आधार पर सिलेंडरों को फिर से भरने में मदद कर सकता है और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर सकता है? क्या वे अन्य देशों की सरकारों से भारत सरकार के पदचिन्हों पर चलने की अपील कर सकते हैं?

• भारत सरकार ने खुले में शौच को रोकने के लिए करोड़ों शौचालय बनाए। इसके परिणामस्वरूप बीमारियों की मात्रा कम हुई है जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए पैसे की बचत हुई है। इतने बड़े फंडिंग के साथ एनजीओ ने क्या भूमिका निभाई?

• गैर सरकारी संगठनों का इरादा और काम करने का रवैया परियोजना को रोकने या कारखाने को बंद करने का नहीं होना चाहिए, यदि किसी पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है, तो उन्हें कंपनी और सरकार के अधिकारियों के साथ उनके समाधान के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। यह वास्तव में गैर सरकारी संगठनों को लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के उनके उद्देश्य में

मदद करेगा।

- यदि सरकार ने नियमों और विनियमों का पालन न करने, वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने के कारण कुछ गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो गैर सरकारी संगठनों, उनकी सहायक एजेंसियों और कुछ मीडिया घरानों को प्रतिबंध का विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार और प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि जनता का पैसा कैसे खर्च किया गया है। सवाल यह है कि क्यों कुछ एनजीओ अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं कर इसे छिपा रहे हैं?

- अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गैर-सरकारी संगठन क्या कर रहे हैं जहां महिलाएं कई अनुचित प्रथाओं से पीड़ित हैं?

- गैर सरकारी संगठनों को वास्तव में योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद और होम्योपैथी के संबंध में इस देश की महान विरासत का अध्ययन करने और दुनिया की बेहतरी के लिए इसे दुनिया भर में फैलाने की आवश्यकता है।

- गैर सरकारी संगठनों को इस दिशा में भी काम करना चाहिए जिसमें नदियों की सफाई और जल प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए धन देना चाहिए।

एक अच्छे सामाजिक उद्देश्य के लिए जुटाई गई धनराशि जिसे किसी अन्य हिस्से के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए या व्यक्तिगत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कामकाज और लेखांकन में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता पर होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी एनजीओ खराब हैं, लेकिन जिनकी मंशा खराब है, सरकार कानूनी और निष्पक्ष भाव के अनुसार उनसे निपटेगी।

एफसीआरए में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण की निगरानी और अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए किए गए संशोधन हैं;

संशोधित कानून के अनुसार एफसीआरए के तहत एनजीओ के पंजीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के आधार नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके अलावा, संशोधनों के साथ, कार्यालय खर्च को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया और चुनावी दावेदारों, सरकारी कर्मचारियों, किसी भी विधायिका के सदस्यों और राजनीतिक दलों को विदेशी धन स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई।

एफसीआरए में संशोधन के बाद जारी नियमों के अनुसार, विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का इरादा रखने वाले गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति कम से कम तीन साल होनी चाहिए और उनके आवेदन से पहले स्वैच्छिक गतिविधियों में 15 लाख की राशि खर्च की जानी चाहिए।

गैर-सरकारी संगठनों को दाता से एक विशिष्ट प्रतिबद्धता पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें विदेशी योगदान की राशि और जिस उद्देश्य के लिए यह प्रस्तावित किया गया है, उसका संकेत दिया जाएगा।

समाज और देश के हित को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अतिरिक्त मकसद या एजेंडे से बचने के लिए गैर सरकारी संगठनों की जवाबदेही सामाजिक और सरकारी मानदंडों के अनुसार तय की जानी

चाहिए। भोले-भाले पश्चिमी लोगों और भारतीयों को किसी भी एनजीओ को दिए जा रहे दान के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। पहले आपको एनजीओ के कामकाज के बारे में गहराई से जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ही आवश्यक मदद के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

संपर्क

पंकज जगन्नाथ जायवाल

7875212161